(ग) इन योजनाओं की निगरानी और उचित कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई प्रणाली के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों को परियोजनाओं की संस्वीकृति सामान्यतया क्षमता के वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन के बाद की जाती है। ये मूल्यांकन कपार्ट के अधिकारियों और बाह्य परियोजना मूल्यांकनकर्ता दोनों द्वारा किये जाते हैं। स्वीकृति आदेश जारी करने के बाद संगठनों को निधियों की पहली किस्त प्रदत्त अनुदान को अधिशासित करने वाली शर्तों के निष्पादन के बाद जारी की जाती है। अगली धनराशियां प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने और वास्तविक रूप में किए गए कार्य का मध्यवर्ती मूल्यांकन करने के बाद जारी की जाती हैं। लम्बी परियोजना अवधि वाली बड़ी परियोजनओं को उनके आकार और प्रकृति के आधार पर एक से अधिक बार निगरानी की जाती है। स्वैच्छिक संगठनों से समय-समय पर कपार्ट को प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है और परियोजना के पूरा होने पर मिलने वाले लाभ, लेखाओं के लेखा-परीक्षित विवरण और उपलब्ध कराए गए अनुदान का उपयोग प्रमाण-पत्र आदि का ब्यौरा देते हुए उनसे कार्य पूरा होने की रिपोर्ट उपलब्ध कराने की भी अपेक्षा की जाती है। इन दस्तावेजों की उचित जांच के बाद परियोजना की उपलब्धियों को रिकार्ड करने के लिए उत्तर-मूल्यांकन कराया जाता है।

"गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान/समर्थन" योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त/समर्पित स्वैच्छिक संगठनों के कार्य निष्पादन का समय-समय पर नियुक्त स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से मूल्यांकन कराया जाता है।

Scheme for development of Agriculture Produce Marketing Committees

873. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT:
SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL:

Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether any proposal has been received from the Gujarat Government for revival of Central Sponsored scheme for development of Agriculture Produce Marketing Committees;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the proposal has been accepted by Government;

(d) if so, the steps taken so far; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) No, Sir.

(b) to (e) Question does not arise.

Computerisation of Land Records

874. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government have launched a scheme for computerisation of Land Records and strenthening of Revenue Administration;

(b) whether updating of land records is also being done in different States;

(c) the progress made in this regard so far, State-wise;

(d) the targets fixed for the same during the Ninth Plan period; and

(e) the funds released by Government during 1996-97 and 1997-98 for this purpose, particularly for the North Eastern States?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) State-wise progress showing the total funds released since inception of the scheme till 1996-97 under the Centrally Sponsored Scheme of Strengthening of Revenue Administration and Updating of Land Records (SRA & ULR) and Computerisation of Land Records (CLR) is enclosed in the statement (*See* below)

(d) The Ninth Plan target is to computerise the land records including cadastral maps in the entire country under the Centrally Sponsored Scheme on Computerisation of Land Records, and thereby generating better services in the field of revenue administration and land management.

(e) In 1996-97, Rs. 26.50 lakhs and Rs. 25.50 lakh were released to Mizoram and Tripura respectively under SRA & ULR and Rs. 80 lakh, Rs. 125 lakh, Rs. 60 lakh and Rs. 15 lakh were released to Assam, Manipur, Mizoram and Tripura respectively under CLR, In 1997-98, Rs. 97.50 lakh have been released to Assam under CLR so far.